राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भारतीय जनता पार्टी के नवनिर्वाचित राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन को पदभार ग्रहण करने पर फूलों का गुलदस्ता भेंट किया तथा बधाई दी।

'प्रशासन यह निर्णय ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

कि इसके लिए पूर्व अनुमति आवश्यक है। स्वामी ने इसे परंपरा का अपमान बताया है।

इसके बाद राज्य प्रशासन ने उन्हें एक नोटिस भेजा, जिसमें उनसे पूछा गया कि वे स्वयं को शंकराचार्य क्यों कहते हैं। नोटिस में सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश का हवाला देते हुए कहा गया कि ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य पद पर उनकी कोई आधिकारिक अभिषेक प्रक्रिया नहीं हुई है। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए शंकराचार्य ने कहा कि ऐसे पदों पर निर्णय केवल अन्य शंकराचार्यों द्वारा लिया जाता है, न कि मुख्यमंत्री या राष्ट्रपति द्वारा। उन्होंने कहा, "चार में से तीन शंकराचार्य पीठों ने मुझे मान्यता दी है। दो पीठों के शंकराचार्य मुझे शंकराचार्य कहते हैं और पिछले कुंभ/मेला में मेरे साथ स्नान भी कर चुके हैं। प्रशासन यह तय नहीं कर सकता कि शंकराचार्य कौन है।"

इस मुद्दे पर विपक्ष ने योगी सरकार पर तीखा हमला बोला है। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा, "जब शंकराचार्य ने मोदी सरकार की आलोचना की, तो उन्हें शाही स्नान से रोक दिया गया और नोटिस जारी कर दिया गया। यह अहंकार की पराकाष्ठा है। क्या अब भारत में गंगा स्नान के लिए भी अनुमति लेनी होगी?" समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने इस नोटिस को अत्यंत निंदनीय बताते हुए कहा कि जो लोग ऐसे प्रमाण मांग रहे हैं, उन्हें पहले अपने ही प्रमाण पत्र साबित करने चाहिए। उन्होंने कहा, "किसी ने नहीं सोचा था कि विभाजनकारी भाजपा इतना नीचे गिर जाएगी।"

सतीश पूनिया ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

प्रभारी बनाया गया है। नितिन नवीन ने आगामी तेलंगाना नगर निगम चुनावों के लिए आशीष शेलार को चुनाव प्रभारी, अशोक परनामी और रेखा शर्मा को चुनाव सह-प्रभारी नियुक्त किया है।

ट्रंप ने ग्रीनलैंड और कैनडा ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

साफ तौर पर सहयोग के बजाय, बल-प्रयोग के रूप में परिभाषित किया।

सरल रूप में, डेवी ने ट्रंप को एक उत्पीड़क के रूप में भी चित्रित किया, जो "सोचते हैं कि यदि आवश्यक हो तो वे बल का उपयोग करके, जो चाहें, वह छीन सकते हैं।"

ट्रंप की पोस्ट्स पर यूरोप, विशेष रूप से डेनमार्क में तेज़ प्रतिक्रिया हुई है, जो ग्रीनलैंड को एक स्वायत्त क्षेत्र के रूप में शासित करता है। घटनाक्रम पर प्रतिक्रिया करते हुए, डेनमार्क के आर्थिक मंत्री ने चेतावनी दी कि अगर तनाव बढ़ता रहा, तो इसे हल्के में नहीं लिया जा सकता।

मंत्री ने कहा, "हम अमेरिका के साथ संवाद करने की कोशिश करेंगे, लेकिन अगर यह बढ़ता रहा, तो यूरोपीय जवाब जरुरी हो जायेगा।

इससे पहले, ट्रंप ने कहा था कि वे ग्रीनलैंड को अमेरिकी क्षेत्र बनाने के अपने नए प्रयास पर यूरोपीय संघ से महत्वपूर्ण प्रतिरोध की उम्मीद नहीं करते। उन्होंने कहा था कि, खासकर रूस और चीन के बढ़ते प्रभाव के बीच, यह आर्कटिक द्वीप राष्ट्रीय सुरक्षा के लिये महत्वपूर्ण है।

फ्लोरिडा में बोलते हुए, ट्रंप ने तर्क दिया कि डेनमार्क के पास ग्रीनलैंड की रक्षा करने की क्षमता नहीं है और उन्होंने अमेरिकी नियंत्रण को रणनीतिक आवश्यकता के रूप में प्रस्तुत किया।

ट्रुथ सोशल पर एक और पोस्ट में, ट्रंप ने नाटो महासचिव मार्क रुटे से ग्रीनलैंड के मुद्दे पर हुई बातचीत का जिक्र भी किया।

ट्रम्प ने लिखा, "मैंने नाटो महासचिव मार्क रुटे से ग्रीनलैंड के बारे में बहुत अच्छी टेलीफोन वार्ता की। ट्रंप ने अमेरिकी सैन्य शक्ति को भी रेखांकित किया तथा कहा कि संयुक्त राज्य अमेरिका पूरी "दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश है।"

उन्होंने कहा, "इसका बड़ा कारण यह है कि मेरे पहले कार्यकाल में हमारी सेना का पुनर्निर्माण हुआ, जो अब और तेज़ी से जारी है। हम एकमात्र ताकत हैं, जो दुनिया भर में शांति सुनिश्चित कर सकते हैं और यह, बहुत सरलता से, शक्ति के माध्यम से किया जाता है।"

अमेरिकी ट्रेजरी सचिव स्कॉट बेसेंट ने मंगलवार को यह विश्वास व्यक्त किया कि संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय देशों के बीच ग्रीनलैंड के अधिग्रहण के मामले में कोई समाधान निकाला जाएगा, और "व्यापार युद्ध" की संभावना को नकारते हुए उन्होंने कहा कि "हिस्टीरिया को शांत किया जाएगा।

बेसेंट ने कहा कि यह मुद्दा हाल ही में उभरा है और इसका ऐसा समाधान निकाला जाएगा, जो संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोप के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करता हो।

बेसेंट ने स्विट्ज़रलैंड के डावोस में विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक के दौरान रिपोर्टर्स से कहा, "48 घंटे का समय है। जैसा कि मैंने कहा है, आराम से बैठकर मीटिंग कीजिये। मुझे विश्वास है कि नेता इस मुद्दे/विवाद को बढ़ाएंगे नहीं और यह बहुत अच्छे स्थान पर समाप्त होगा।"

'पेपर ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

की तथ्यात्मक रिपोर्ट बंद लिफाफे में पेश की, जिसका एकलपीठ में याचिकाकर्ता रहे अभ्यर्थियों के वकील हरेन्द्र नील ने विरोध किया। इस पर खंडपीठ ने उनसे पूछा कि एसओजी की ओर से भर्ती रद्द करने के संबंध में 13 अगस्त, 2024 की गोपनीय रिपोर्ट उन्हें कैसे मिली।

इसके जवाब में कहा गया कि मामले में स्वयं राज्य सरकार ने ही जांच नहीं की है।

इस पर अदालत ने एडीजी विशाल बंसल से पूछा कि एसओजी की गोपनीय रिपोर्ट बाहर कैसे आई। वहीं अदालत ने पूछा कि एकलपीठ में याचिकाकर्ता रहा एक अभ्यर्थी एसओजी में नियुक्त है, तो क्या उसने रिपोर्ट दी है।

इस पर एडीजी और अभ्यर्थियों के वकील ने कहा कि संबंधित अभ्यर्थी एसओजी में नियुक्त है, लेकिन वह जांच टीम का सदस्य नहीं था। बंसल ने कहा कि रिपोर्ट एसओजी ऑफिस से लीक नहीं हुई है और इस बारे में हम जांच कर रहे हैं। इस पर अदालत ने टिप्पणी करते हुए कहा कि लगता है कि एसओजी ऑफिस भी मिलीभगत में शामिल हो गया है।

यूरोप, भारत के ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

की, जो सीधे तौर पर डॉनल्ड ट्रंप द्वारा यूरोप पर किए जा रहे हालिया हमलों के संदर्भ में अमेरिका के लिए था। वॉन डेर लेयेन ने कहा कि यूरोप भारत के साथ व्यापक आर्थिक संबंध स्थापित करने को लेकर उत्सुक है, क्योंकि भारत तेज़ी से प्रगति कर रहा है। उन्होंने कहा कि एक ओर यूरोप भारत के विशाल और तेजी से बढ़ते बाजारों का लाभ उठाना चाहता है, वहीं दूसरी ओर वह भारत को अपनी सर्वश्रेष्ठ क्षमताएं और उत्पाद भी उपलब्ध कराएगा। ऐसे समय में जब भारत-अमेरिका व्यापार वार्ता ठहराव की स्थिति में है, वॉन डेर लेयेन ने रेखांकित किया कि इस व्यापार समझौते के माध्यम से यूरोपीय यूनियन को "पहला कदम उठाने का लाभ" मिलेगा, एक ऐसे क्षेत्र में, जो अत्यंत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है और बढ़ते आर्थिक व रणनीतिक अवसर प्रदान कर रहा है। भारत-ईयू व्यापार समझौते के परिणामस्वरूप, यूरोप के उत्पादों की एक व्यापक श्रृंखला बहुत कम शुल्क पर भारतीय बाजार में प्रवेश कर सकेगी, जिससे भारत के तेजी से बढ़ते मध्यम वर्ग के विशाल बाजार के बड़े हिस्से खुल जाएंगे। साथ ही, यूरोपीय संघ ने भारत की व्यापारिक संवेदनशीलताओं का भी ध्यान रखा है। इन्हीं कारणों से भारत-ईयू व्यापार समझौते में कृषि क्षेत्र, चीनी उद्योग और कुछ अन्य उत्पादों को शामिल नहीं किया जाएगा। भारत द्वारा यूरोपीय शराब और वाइन पर लगाए गए ऊंचे शुल्कों में कटौती की जाएगी, जबकि यूरोप के कुछ ग्लोबल इंडीकेटर्स उत्पादों (वे उत्पाद जो किसी खास जगह पर बनने के कारण उस जगह के नाम से जाने जाते हैं) को इस समझौते से बाहर रखा जाएगा। यह घोषणा वैश्विक अर्थव्यवस्था के पुनर्संरेखण को स्वीकार करते हुए तेज़ी से आगे बढ़ने और एक नई व्यवस्था की आवश्यकता को रेखांकित करती है। इसमें कोई संदेह नहीं कि इक्कीसवीं सदी में भारत कई यूरोपीय देशों की तुलना में कहीं अधिक महत्वपूर्ण खिलाड़ी बनकर उभरा है, जबकि उनमें से कई देश इस दौर में अपेक्षाकृत छोटे पड़ गए हैं।

'पार्टी में ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

उन्होंने आगे कहा, "अब माननीय नितिन नबीन जी हम सबके अध्यक्ष हैं और उनकी जिम्मेदारी केवल भाजपा को संभालने की ही नहीं, बल्कि एनडीए के सभी सहयोगी दलों के बीच समन्वय सुनिश्चित करने की भी है।" मोदी ने कहा, "नितिन जी में युवा ऊर्जा भी है और व्यापक अनुभव भी।"

कर्मचारी ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

आरोपियों ने अपने स्तर पर अभ्यर्थियों से रुपए लेकर उनके नंबर बढ़ाए हैं।

एसओजी की पड़ताल में सामने आया है कि गिरफ्तार अभ्यर्थी पूनम माथुर के परीक्षा में महज 63 नंबर आए थे। जबकि संजय माथुर ने ओएमआर शीट में हेराफेरी कर उसके 182 नंबर कर दिए। अन्य अभ्यर्थियों के नंबर में भी बढ़ोतरी की गई है। उन्होंने बताया कि इस कंपनी ने और किन परीक्षाओं में ओएमआर शीट स्कैन करने का काम किया है. इसकी जांच भी जारी है। चयन बोर्ड के दोनों अधिकारी भी लंबे समय से परीक्षा के गोपनीय कार्य से जुड़े हुए थे।

एसओजी की पड़ताल में सामने आया है कि 2019 में उत्तर प्रदेश की एसटीएफ ने लखनऊ में शादान और विनोद को गिरफ्तार किया था। उनके पास करीब 60 लाख रुपए की संदिग्ध नकदी और कर्मचारी चयन बोर्ड की परीक्षाओं के 18 अभ्यर्थियों के नाम मिले थे। उस मामले की जांच आगे नहीं बढ़ पाई। एसओजी ने उस इनपुट के आधार पर अपनी जांच को आगे बढ़ाते हुए यह कार्रवाई की है।

फिक्की की वित्तीय वर्ष ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

अनुपालन जैसी परिचालन चुनौतियों के कारण कंपनियां सतर्क बनी हुई हैं।

भंडारण (इन्वेंट्री) स्तर स्थिर होते दिख रहे हैं, जहां पिछली तिमाही की तुलना में कम कंपनियों ने भंडार ऊंचा बने रहने की उम्मीद जताई है। रोजगार सृजन के इरादों में भी मामूली सुधार देखा गया है और 38 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने आने वाले महीनों में नए कर्मचारियों को जोड़ने की योजना बताई, जबकि एक वर्ष पहले यह आंकड़ा 35 प्रतिशत था। हालांकि अधिकांश कंपनियों ने बड़े पैमाने पर श्रम की कमी की सूचना नहीं दी, फिर भी कुशल श्रमिकों की उपलब्धता को लेकर चिंता बनी हुई है, जो कार्यबल की तैयारी में संरचनात्मक कमियों को उजागर करती है।

निर्माताओं के लिए वित्तीय स्थितियां कुल मिलाकर सहायक बनी हुई हैं। उत्तरदाताओं द्वारा बताई गई औसत ब्याज दर 8.9 प्रतिशत रही, और 87 प्रतिशत से अधिक ने कार्यशील पूंजी और दीर्घकालिक निवेश, दोनों के लिए बैंक वित्त की पर्याप्त उपलब्धता की जानकारी दी। हालांकि, लागत दबाव एक प्रमुख चिंता बना हुआ है। लगभग 57 प्रतिशत कंपनियों ने बिक्री के अनुपात में उत्पादन लागत बढ़ने की बात कही, जिसका कारण कच्चे माल की ऊंची कीमतें, मुद्रा अवमूल्यन तथा परिवहन और उपयोगिता लागत में वृद्धि है।

विकास के दृष्टिकोण से, सर्वेक्षण के निष्कर्ष भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए सकारात्मक संकेत देते हैं। मजबूत विनिर्माण उत्पादन, बेहतर मांग स्थितियां और बढ़ता क्षमता उपयोग आमतौर पर उच्च औद्योगिक जीडीपी, बेहतर रोजगार संभावनाओं और मजबूत निवेश चक्र में तब्दील होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल्स में मजबूत वृद्धि तथा अन्य अधिकांश विनिर्माण क्षेत्रों में मध्यम विस्तार की उम्मीद यह दर्शाती है कि वित्त वर्ष 26 में औद्योगिक वृद्धि व्यापक आधार वाली रहने की संभावना है, न कि केवल कुछ क्षेत्रों तक सीमित।

यदि यह गति बनी रहती है, तो यह वैश्विक अस्थिरता के खिलाफ अर्थव्यवस्था को महत्वपूर्ण सुरक्षा प्रदान कर सकती है, सरकारी राजस्व को समर्थन दे सकती है और आने वाली तिमाहियों में भारत को विनिर्माण-आधारित विकास इंजन के रूप में और मजबूत कर सकती है।

स्ट्रीट डॉग्स पर ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

है कि उसने अवमानना की कार्यवाही नहीं की।

अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि जब उसने कुत्तों को खाना खिलाने वालों को आवारा कुत्तों के हमलों के लिए जिम्मेदार ठहराने की बात कही थी, तो वह व्यंग्य में नहीं, बल्कि पूरी गंभीरता से कही गई थी।

पीठ ने मेनका गांधी की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता राजू रामचंद्रन से कहा, "थोड़ी देर पहले आप अदालत से कह रहे थे कि हमें संयम बरतना चाहिए।

क्या आपने यह देखा कि आपकी मुवक्किल किस तरह की टिप्पणियां कर रही हैं? आपकी मुवक्किल ने अवमानना की है। हम उस पर संज्ञान नहीं ले रहे हैं-यह हमारी उदारता है। क्या आपने उनका पॉडकास्ट सुना है? उनकी बॉडी लैंग्वेज कैसी है? वह क्या कहती हैं और किस तरह कहती हैं?"

राहुल को मिला फिरोज़ गांधी का ड्राइविंग लाइसैंस

रायबरेली, 20 जनवरी। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को मंगलवार को उत्तर प्रदेश के रायबरेली में एक व्यक्ति ने उनके दादा फिरोज गांधी का ड्राइविंग लाइसेंस सौंपा। अपने संसदीय क्षेत्र के दौरे पर आए कांग्रेस नेता राहुल गांधी को दौरे के दूसरे दिन विकास सिंह नामक एक व्यक्ति ने फिरोज गांधी का ड्राइविंग लाइसेंस सौंपा। विकास ने यह लाइसेंस सहेजकर रखा हुआ था। रायबरेली प्रीमियर लीग के आयोजक मंडल के सदस्य विकास सिंह ने बताया कि वर्षों पहले एक कार्यक्रम के दौरान उनके ससुर को अचानक यह ड्राइविंग लाइसेंस मिला था। तब से उन्होंने इसे सहेजकर रखा हुआ है। सिंह ने कहा कि जब उनके ससुर की मृत्यु हो गई तो उसके बाद उनकी सास ने भी इसे संभाल कर रखा। विकास सिंह ने बताया कि इस बार राहुल गांधी के आने की जानकारी हुई तो उनकी सास ने कहा कि उनकी (राहुल गांधी) एक अमानत मेरे पास रखी है और इसे उन्हें ले जाकर दे दो। विकास सिंह ने मंच पर राहुल गांधी को यह लाइसेंस दिया तो वे उसे देखते रहे और तुरंत वहीं से अपनी मां सोनिया गांधी को सोशल मीडिया के जरिये लाइसेंस की एक फोटो भेजी।

राष्ट्रदूत (एचयूएफ) के लिए मुद्रक एवं प्रकाशक सोमेश शर्मा द्वारा मैसर्स अरावली प्रिन्टर्स, राष्ट्रदूत भवन, चुंगी नाका के पास, अजमेर (राजस्थान) से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादक-राजेश शर्मा, आर.एन.आई. नं. 65015/96, जयपुर कार्यालय: सुधर्मा एम.आई.रोड, जयपुर। फोन: 2372634, 4103333-34 फैक्स : 0141-2373513, कोटा कार्यालय : पलायथा हाऊस, छत्रपति शिवाजी मार्ग, कोटा। फोन: 2386031, 2386032,फैक्स:0744-2386033, उदयपुर कार्यालय: आयड मैन रोड आयड, उदयपुर। फोन: 2413092, फैक्स : 0294-2410146, बीकानेर कार्यालय : कुम्भाना हाऊस, हनुमान हत्था, बीकानेर। फोन: 2200660, फैक्स 0151-2527371, जालोर कार्यालय :- जी 1/63, इन्डस्ट्रीयल एरिया, फेस प्रथम, जालोर। फोन: 226422, 226423, फैक्स: 02973-226424 हिण्डौनसिटी कार्यालय :- जी -1-201, रीको औद्योगिक क्षेत्र, हिण्डौनसिटी। फोन: 230200, 230400, फैक्स: 07469-230600 चूरू कार्यालय : एच-150, रीको औद्योगिक क्षेत्र, चूरू, फोन : 256906, 256907, फैक्स: 01562-256908